

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक ०५ फरवरी, 2023

विषय:-प्रदेश में निराश्रित गोवंशों के संरक्षण एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु महोदय,

आप अवगत है कि निराश्रित गोवंश का शत-प्रतिशत संरक्षण एवं उनका भरण-पोषण वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2264/सैतीस-2-2022, दिनांक 07.11.2022 एवं शासनादेश संख्या-05/सैतीस-2-2023-5(53)/18-टी०सी०-2, दिनांक 04.01.2023 द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-1/261484/2023, दिनांक 13.01.2023 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवशेष निराश्रित गोवंश को दिनांक 31.03.2023 तक शत-प्रतिशत संरक्षित किये जाने तथा जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न बिन्दु पर कार्यवाही प्राथमिकता पर किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का आच्छादन अधिकाधिक किया जाय, तथा इच्छुक पशुपालकों को गोवंश उपलब्ध कराने में तेजी लायी जाय। जिलाधिकारी के त्रैमासिक रीपॉर्टर के अनुसार फील्ड में समय से निरीक्षण/रात्यापन कराया जाय। गो पालकों की मांग लम्बित न रहें तथा नियमित रूप से डी०बी०टी० के माध्यम से समयबद्ध भुगतान कराया जाय एवं अबतक भुगतान न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय।
- (2) मुख्यमंत्री पोषण योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल-विकास विभाग द्वारा चिन्हित कुपोषित परिवारों को ब्यायी हुई गाय उपलब्ध करायी जाय, जिससे सुपोषण हेतु उन परिवारों को दूध उपलब्ध हो सके, इस योजना को जिलाधिकारी सहित प्रत्येक स्तर पर समीक्षा की जाय।
- (3) कृत्रिम गर्भाधान योजना द्वारा नरल सुधार हेतु व्यापक रूप से पशुओं का आच्छादन किया जाय, तथा नरल सुधार के प्रचलित मिशन 75 लाख टीकाकरण अभियान रोकस सार्टेड सीमेन के आच्छादन एवं इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने की भी समीक्षा की जाय।
- (4) गो संरक्षण केन्द्रों में गोबर से पेन्ट, सी०बी०जी० के उत्पाद के साथ इन्हें प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाय।
- (5) गो-आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन हेतु इच्छुक गैर-सरकारी संस्थाएँ एवं अन्य संगठनों के साथ एम०ओ०यू० किया जाय। इन संस्थाओं को गो संरक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु लीज पर नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

- (6) निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने एवं परिवहन हेतु कैटिल-कैंचर का क्रय तत्काल किया जाय। निराश्रित गोवंश को गो-संरक्षण स्थलों में संरक्षित किये जाने की व्यवस्था में तेजी लाया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं अवशेष स्थलों का निर्माण अविलम्ब पूर्ण कराया जाय।
- (7) जनपद में स्थापित/संचालित गो आश्रय स्थलों/केंद्रों की क्षमता एवं उनमें संरक्षित गोवंश का औचक निरीक्षण किया जाय एवं क्षमता के अनुरूप ही गोवंशों का संरक्षण किया जाय। विद्यमान गो आश्रय स्थलों के विस्तारीकरण का भी मौके पर सत्यापन कराया जाय, जिससे रायबरेली जनपद जैसी overcrowding की समस्या न हो।
- 3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने स्तर पर शीर्ष समीक्षा बैठक आहूत कर ले एवं कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा. रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

प0सं0-290(1)/सैंतीस-2-2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पशुधन विभाग, उ0प्र0।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।